	a" -	70	70		
	ALL I	NATION IAX MARKET MARKET ::आयुक्त (अपील्स) का कार्यालय, वस्तु एवं सेवा कर और केन्द्रीय उत्पा O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), GST & CENTRAL ES द्वितीय तल, जी एस टी भवन / 2 <sup>st</sup> Floor, GST Bhavan, देखतीय तल, जी एस टी भवन / 2 <sup>st</sup> Floor, GST Bhavan, रेस कोर्स रिंग रोड, / Race Course Ring Road, <u>राजकोट / Rajkot – 360 001</u> Tele Fax No. 0281 – 2477952/2441142 Email: cexappealsrajkot@g	KCISE,		
	<u>रजिस</u> क	нтім чаза жалі на зтім чаза жалі   Арреа! Гніе № У.2/350/RAJ/2017   УТІЛ. 2017 У.2/350/RAJ/2017   УПІЛ. 2017 У.2/350/RAJ/2017	दिलाक। Dute 06.12.2016		
a shule shake theat (Order-In-Appeal No.):					
		<u>RAJ-EXCUS-000-APP-081-2017-18</u> आदेश का दिनांक / 28.09.2017 जारी करने की तारीख /	तारीख / 03 10 2017		
		Date of Order: Date of issue: 03.10.2017 कुमार संतोष, आयुक्त (अपील्स), राजकोट द्वारा पारित / Passed by Shri Kumar Santosh, Commissioner (Appeals), Rajkot			
	ग	अपर आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त/ सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ संवाकर, राजकोट / जामनगर / गांधीधाम। द्वारा उपरलिखित जारी मूल आदेश से सुजित / Arising out of above mentioned OIO Issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Central Excise / Service Tax, Rajkot / Jamnagar / Gandhidham			
	घ	अपीलकर्ता & प्रतिवादी का नाम एवं पता /Name&Address of the Appellant & Respondent :- M/s. Backbone Gold Flat Owner Association, Opposition Raj Palace., University Road.,Sadhu Vasvani RoadRajkot- 360005			
	2.43	इस आदेश(अपील) से व्यथित कोई व्यक्ति तिम्नलिखित तरीके में उपयुक्त प्राधिकारी / पाधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है।/ Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way.			
अतर्गत एवं विस्त आधानयम, 1994 को धारा 86 के अतर्गत निम्नोलिखित जगह		सीमा शुल्क केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आं अंतर्गत एवं वित्त अपिनियम, 1994 की धारा 86 के अंतर्गत निम्नतिखित जगह की जा सकती है ॥ Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944			
	0	वर्गीकरण मूल्यांकन से सम्बन्धित सभी मामले सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकर 2. आर के पुरम, नई दिल्ली, को की जानी चाहिए ।/ The special bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No. 2. R matters relating to classification and valuation.			
	(ii)	उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में बताए गए अपीलों के अलावा शेष सभी अपीलें सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एव (सिस्टेंट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, , दवितीय तल, बहुमाली भवन असावां अहमदाबाट- ३८००१६ को की जानी चाहिए To the West regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at . Asarwa Ahmedabad-380016 in case of appeals other than as mentioned in para- 1(a) above	11		
	(16)	अपौलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील पश्तुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के नि मये प्रपत्र EA-3 को चार प्रतियों में दर्ज किया जाना चाहिए । इनमें से कम से कम एक पति के साथ. जहां उत्पाद और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संखरन करे। निर्धारित शुल्क न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्टार के नाम से किसी भी सावैजिनक क्षेत्र के वैक द्वारा जरी रेखाकिस बिक संबंधित झुफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहा संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित। लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा ।/	शुलक की मॉग डयाज की मॉग में अधिक है तो कमश: 1,000/- का भुगतान, संबंधित अपीसीय		
		The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in guadruplicate in form EA-3 / as prescribe Excise (Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against one which at least should be ac 1,000/- Rs 5000/ Rs 10,000/- where amount of duty demand/interest/penalty/refund is upto 5 L above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asst. Registrar of bran sector bank of the place where the bench of any nominated public sector bank of the place where is situated. Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs 500/	companied by a fee of Rs. ac., 5 Lac to 50 Lac and		
	(B)	अपीलीय ल्यायाधिकरण के समझ अपील, विस्त अधिनियम, 1994 की धारा 86(1) के अतर्गत सेवाकर नियमवाली. निर्धारित प्रयत्र S.IS में चार पतियों में की जा सकेगी एव उसके लाथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो. (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और इनमें से कम एक पति के साथ. जहां सेवाकर की मांग ह जुमीना, रुपए 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो रुपये अथवा 10.000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संतरन करें। निर्धारित शुल्क का मुगतान, संबंधित अपी सहायक रजिस्टार के लाम से किसी भी सार्वजिनक क्षेत्र के बैंक दवारा जारी रेखाकेत बैंक ड्राप्ट दवारा किया जाना चार् बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां मर्बापित अपीलीय ल्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थरन आदेश (स्टे ऑ 500/- रुपए का निर्धारित जुल्क जमा करना होगा।// The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act. 1994, to the Appellate quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1934, and 5 copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accon 1000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied of Rs 5 Lakhs or	उसकी पति साथ में सलरन करें याज की मॉग और लगाया गया कमश 1.000/- रुपये, 5,000/- लिय न्यायाधिकरण की शाखा के रेए । संवधित हाफर का मुयतान, डेर) के लिए आवेटन पत्र के साथ Tribunal Shall be filed in Shall be accompanied by a		
		amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five lakhs but not Rs 10.000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than form of crossed bank draft in favour of the Assistant Registrar of the bench of nominated Public where the bench of Tribunal is situated. / Application made for grant of stay shall be accompanied	less Rs 5000/- where the exceeding Rs Fifty Lakhs, h fifty Lakhs rupees, in the Section 2010		

-

....2....

.

- वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 की उप-धाराओं (2) एवं (2A) के अंतर्गत दर्ज की गयी अपील, सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(2) एवं (i) 9(2A) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-7 में की जा सकेगी एवं उसके माथ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुरूक अथवा आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुरूक दवारा पारित आदेश की प्रतियाँ सलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी थाहिए) और आयुक्त द्वारा सहायक आयुक्त अयवा उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर, को अपीक्षीय ज्यायाधिकरण को आवेदन दर्ज करने का निर्देश देने वाले आदेश की प्रति भी साथ में संवयन करनी होगी । / The appeal under sub section (2) and (2A) of the section 86 the Finance Act 1994, shall be filed in For ST.7 as prescribed under Rule 9 (2) & 9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner
  - Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissioner authorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise/ Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal.
- सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एव सेवाकर अपीलीय पाधिकरण (सेस्टेट) के प्रति अपीलों के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 35एफ के अंतर्गत, जो की वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत संधाकर को भी लागू की गई है, इस आदेश के प्रति अपीलीय (ii) प्राधिकरण में अपील करते समय उत्पाद शुल्कलेवा कर मांग के 10 प्रतिशत (10%), जब मांग एव जुमोना विवादित है, या जुमीना, जब केवल जुमीना विवादित है, का भुगतान किया जाए, बशर्त कि इस धारा के अतर्गत जमा कि जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रुपए में अधिक न हो।
  - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत "मांग किए गए शुल्क" में निम्न शामिल है. धारा 11 डी के अंतर्गत रकम
  - (i)
  - सेनवेट जमा की ली गई गलत राशि (ii) सेतवेट जमा तियमावली के नियम 6 के अलगैल देय रक्तम

(iii) - बंशतें यह कि इस धारा के प्रावधान वित्तीय (स. 2) अधिनियम 2014 के आरंभ से पूर्व किसी अपीलीय पाधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्थगत अर्जी एवं अपील को लागू नहीं होगे।/

For an appeal to be filed before the CESTAT, under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 83 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute, provided the amount of pre-deposit payable would be subject to a ceiling of Rs. 10 Crores.

- Under Central Excise and Service Tax. "Duty Demanded" shall include amount determined under Section 11 D: 63
- amount of erroneous Cenvat Credit taken;
- (11) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules. (iii)

- provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.

#### आरत सरकार को पनरीक्षण आवेदन

#### (C)

Revision application to Government of India: इस आदेश की पुनरीक्षण याचिका निम्नलिखित मामलों में, केंद्रीय उत्पाद शुलक अधिनियम, 1994 की घारा 35EE के पंथम परंतुक के अतर्गत अंवर सचिव, भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन इंकाई, वित्त महालय, राजस्व विभाग चौथी मजिल जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, को किया जाना चाहिए। /

A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Dethi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35B ibid:

यदि माल के किसी नुकसान के मामले में जहां नुकसान किसी माल को किसी कारखाने से भंडार गृह के पारगमन के दौरान या किसी अन्य कारखाने या फिर किसी एक भंडार गृह से दूसरे भंडार गृह पारगमन के दौरान था किसी भंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसम्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में माल के नुकसान के मामले में।/ (i) In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one

warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse

- भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को नियांत कर रहे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर भरी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छुट (रिबेट) के सामले में, जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को नियांत की गंगी है। / (ii). In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.
- यदि उत्पाद शुरुक का भगतान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या भूटान को माल नियोत किया गया है। / (iii)
- In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan without payment of duty.
- सुनिश्चित उत्पाद के उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो इयूटी केडीट इस अधिनियम एवं इसके विभिन्न पावधानों के तहत मान्य की गई है और ऐसे अंदिश जो आयुक्त (अपील) के द्वारा वित्त अधिनियम (न. 2), 1998 की धारा 109 के द्वारा नियत की गई तारीख अथवा समायाविधि पर या बाद में पारित किए गए है।/ (iv)

Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

- उपरोक्त आवेदन की दो प्रतिया प्रपंच संख्या EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के लियम 9 के अंतर्गत विनिदिष्ट है, इस आदेश के संप्रेषण के 3 माह के अंतर्गत की जानी चाहिए । उपरोक्त आवेदन के साथ मूल आदेश व अपील आदेश की दो प्रतिया सलम्न की जानी चाहिए। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-EE के तहन निर्धारित शुल्क की अदायगी के साध्य . के तौर पर TR-6 की प्रति (v) संलग्न की जानी चाहिए। / The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.
- पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्नतिखित निर्धारित शुल्क की अदायगी की जानी चाहिए । जहां सलग्न रकम एक लाख रूपये या उससे कम ही तो रूपये 2007 का भुगतान किया जाए और यदि सलग्न रकम एक लाख रूपये से ज्यादा हो तो रूपये 1000 न का मुगतान किया जाए । The entering (vi) The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.
- यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश हैं तो पत्येक मूल आदेश के लिए शुरुक का भगतान, उपयुंक्त ढंग से किया जाना चाहिये। इस तष्ठ्य के होते हुए भी की लिखा पदी कार्य से बचने के लिए यधास्थिति अपीसीय नयापिकरण को एक अपीस या कैदीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है। / In case, if the order covers various numbers of order- in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, not withstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each. (D)
- ययासशोधित न्यायालय शुरुक अधिनियम, 1975, के अनुसूची-1 के अनुसार मूल आदेश एवं स्थगन आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का न्यायालय शुरुक टिकिट लगा होना वाहिए। 7 (E) One copy of application or 0.1.0 as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs. 6.50 as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act. 1975, as amended.
- सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर सपीलीय न्यायाधिकरण (कार्य विधि) सियमावली, 1982 में वर्णित एव अन्य संबन्धित मामलों को समिमलित करने वाले नियमों की और भी ध्यान आकर्षित किया जाना है। / Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service (F) Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.
- उच्च अपीलीय प्राधिकारी को अपील दाखिल करने से संबंधित व्यापक, विंस्तृत और नवीनतम प्रावधानों के लिए, अपीलायौं विभागीय वेबसाइट (G) www.cbec.gov.in 최 효과 관계 문 이가 이가 이가 이가 이가 하는 것 같아요. 이 가지 않는 것 같아요. 이 가지 않는 것 같아요. The appellant may For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website www.cbec.gov.in

3

### :: MISCELLENOUS ORDER ::

An application for rectification of mistake (in short, ROM Application) was filed under Section 74 of the Finance Act, 1994 by M/s. Backbone Gold Flat Owners Association, Opp. Raj Palace, University Road, Sadhu Vasvani Road, Rajkot-360 005 (hereinafter referred to as "the applicant"), against the Order-In-Appeal No. RAJ-EXCUS-000-APP-092-2016-17 dated 06.12.2016 passed by the then Commissioner (Appeals-III), Central Excise, Rajkot.

2. The applicant, being aggrieved with the impugned OIA filed this ROM application, *inter alia*, contending that vide para 8 of the impugned OIA the appeal was allowed by observing that no service tax was payable on the amount collected after legal and formal existence of the applicant and the date of legal and the formal existence of the Association determining that date as 20.07.2013, whereas the Applicant came into existence w.e.f. 09.08.2010 as is evident from facts on record that M/s. Backbone Gold Flat Owners' Association was incorporated on 09.08.2010 as is evident from :-

(i) Registration Deed dated 09.08.2010 before sub-registrar, Raiya, Rajkot for registration of 'Backbone Gold Flaw Owners Association';

 PAN card issued by Income Tax department to Backbone Gold Flat Owners Association showing their existence from 09.08.2010 and showing it as their Date and Birth; and

(iii) Copy of Income Tax filed by them showing date of birth/incorporation as 09.08.2010.

2.1 The applicant stated that in view of the above facts the mistake of treating date of incorporation of the Applicant as 20.07.2013 in the OIA, needs to be corrected as 09.08.2010.

3. Personal hearing in the matter was held on 25.09.2017. S/Shri R. C. Prasad, Consultant and Sanjay M. Makadia, President of the applicant appeared and reiterated submissions made by the applicant in the ROM application; that they also submitted copy of PAN card and Income Tax Return for AY 2015-16 showing date of incorporation as 09.08.2010; that they also submitted Deed of incorporation showing date of incorporation as 09.08.2010. No one appeared from the Department, even though personal hearing notice was sent to them. ν.

4. I have carefully gone through the facts of the case, impugned OIA, facts stated in of ROM application and submissions made by the applicant during the personal hearing.

5. The limited point to be decided is that whether there is any mistake in the OIA apparent from the record and whether it requires rectification in the impugned OIA. The applicant has contended that the date of incorporation of the applicant i.e. M/s. Backbone Flat Owners Association is 09.08.2010, and not 20.07.2013, as stated in para (7) in the impugned OIA. The relevant portion of the OIA is reproduced below as under :-

"7..... Thus, it is evident that the amount was collected by the developer in the guise of the Resident Association prior to the said Association come into existence. I also find from the recorded proceedings that on 20.07.2013, meeting of the flat owners was called for and executive members were nominated.

Thus, I am of the view that the effectively, association come into operation 20.07.2013 and amounts were collected way ahead of formation of the association......"

6. On going through the records of the case, the impugned OIA and the application filed by the applicant, I find that there is a mistake crept in the impugned OIA wherein the benefit has been granted with effect from 20.07.2013, treating this date as the date of incorporation, whereas the date of incorporation of the Association is 09.08.2010 before the sub-registrar, Raiya, Rajkot and also as per PAN Card issued by the Income Tax Department of Government of India.

7. I find that the Section 74 of the Finance Act, 1944 permits correction in the order already passed by the appellate authority in case of "mistake apparent from the record". I also find that the statutory documents, viz, Income Tax Return and Declaration under Gujarat Ownership Flat Act, 1973 submitted by the applicant before this office along with ROM application, delineated at para (2) of this order, clearly goes to demonstrate that the date of incorporation is 09.08.2010, and therefore findings at Para (7) of the impugned OIA that M/s. Backbone Gold Flat Owners' Association came into operation on 20.07.2013, is a mistake in the order.

18/9/2011

8. In view of the above facts and statutory documents, I find that the correct date of incorporation should be 09.08.2010, and therefore there is mistake apparent from

Page No. 4 of 5

the records, and hence this ROM application filed by the applicant under Section 74 of the Finance Act, 1994 merits acceptance to the extent of seeking correction in the date of incorporation. Needless to say that the rest of the findings of the impugned order, remain unaltered.

9. आवेदक द्वारा दर्ज की गई ROM आवेदन का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।

9. The ROM filed by the applicant stands disposed off in above terms.

आयुक्त (राजकोट)

# By R.P.A.D.

To,

M/s. Backbone Gold Flat Owners' Association, Opp. Raj Palace, University Road, Sadhu Vasvani Road, Rajkot-360 005

मेसर्स बॅकबोने गोल्ड फ्लॅट औनेर्स असोशिएशन, ओपो राज पैलेस, यूनिवरसिटि रोड, साधू वासवानी राजकोट - 360 005,

## Copy to:

- 1. The Chief Commissioner, GST & Central Excise, Ahmedabad.
- The Commissioner, GST & Central Excise, Rajkot.
- 3. The Assistant Commissioner, GST Division-I, Rajkot.
- The Jurisdictional Superintendent, Division-I Range office, Rajkot
- 5. Guard File.